

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 06 भाग 02, (जुलाई, 2026)
पृष्ठ संख्या 21-23



आम की खेती एवं निर्यात: भारतीय किसानों
के लिए अवसर और चुनौतियाँ

इशिता उमर¹, सुप्रिया², प्रतीक कुमार³
एवं दीपनारायण यादव⁴

¹पीएच.डी. स्कॉलर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग,

²एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग,

³पीएच.डी. स्कॉलर, कृषि विस्तार शिक्षा विभाग,

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत।

Email Id: – ishitaissu60@gmail.com

परिचय

आम भारत की कृषि, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। भारत को आम का उद्गम स्थल माना जाता है और आज भी देश विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक है। भारत में लगभग 2.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती की जाती है तथा देश का वार्षिक उत्पादन 28-30 मिलियन टन के आसपास है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

उत्तर प्रदेश का दशहरी और चौसा, बिहार का जर्दालू, गुजरात का केसर तथा महाराष्ट्र का अल्फांसो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। कृषि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से आम केवल एक फल नहीं है, बल्कि यह लाखों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, कृषि निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की नीति में आम को एक रणनीतिक बागवानी फसल माना जाता है।

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में आम का महत्व

भारत में आम की खेती लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का आधार है। अन्य वार्षिक फसलों की तुलना में आम एक दीर्घकालिक बागवानी निवेश है, जो एक बार स्थापित होने के बाद कई दशकों तक उत्पादन देता है। आम उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी मूल्य श्रृंखला— जैसे पौध उत्पादन, बाग प्रबंधन, तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और प्रसंस्करण ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रोजगार सृजित करती है। यही कारण है कि आम को उच्च मूल्य वाली बागवानी फसल के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और कृषि विविधीकरण कार्यक्रमों में भी आम की खेती को किसानों की आय बढ़ाने के प्रभावी साधन के रूप में महत्व दिया गया है। आम से जूस, पल्प, अचार, स्क्वैश, कैंडी और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण करके अतिरिक्त मूल्य संवर्धन भी किया जाता है, जिससे किसानों और उद्यमियों दोनों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

आम निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन

भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक होने के बावजूद निर्यात के क्षेत्र में अपनी संभावनाओं

का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया है। फिर भी भारतीय आमों की मांग संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लगातार बनी हुई है। निर्यात के माध्यम से किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त होता है, विशेषकर अल्फांसो, केसर और दशहरी जैसी प्रीमियम किस्मों के लिए। कृषि निर्यात संवर्धन एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के अनुसार भारत प्रतिवर्ष हजारों टन ताजे आमों का निर्यात करता है, जिससे करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। निर्यात से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि कृषि क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता भी मजबूत होती है।

वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति

यद्यपि भारत विश्व उत्पादन में अग्रणी है, फिर भी वैश्विक आम निर्यात में उसका हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। मेक्सिको, पेरू, ब्राजील और थाईलैंड जैसे देश निर्यात के क्षेत्र में भारत से आगे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशों ने गुणवत्ता नियंत्रण, कोल्ड चेन, पैकेजिंग, ट्रेसबिलिटी और निर्यात अवसंरचना पर व्यापक निवेश किया है। भारत में उत्पादन की विशाल क्षमता होने के बावजूद कटाई उपरांत प्रबंधन की कमजोरियाँ, उच्च लॉजिस्टिक लागत और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का सीमित अनुपालन निर्यात वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाए, तो वह वैश्विक आम व्यापार में अपनी हिस्सेदारी कई गुना बढ़ा सकता है।

जापान का बाजार और उसका महत्व: 1986 का प्रतिबंध और 2006 में पुनः प्रवेश

जापान विश्व के सबसे आकर्षक और उच्च मूल्य वाले कृषि आयात बाजारों में से एक है। जापानी उपभोक्ता गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और उत्पाद की ट्रेसबिलिटी को अत्यधिक महत्व देते हैं। भारतीय आमों, विशेषकर अल्फांसो और केसर, को जापान में प्रीमियम श्रेणी के फल के रूप में देखा जाता है। यद्यपि जापान में निर्यात की मात्रा मध्य-पूर्वी देशों की तुलना में कम है, लेकिन वहां प्राप्त होने वाला मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए जापानी बाजार में प्रवेश भारतीय आम उत्पादकों और निर्यातकों के लिए प्रतिष्ठा तथा आर्थिक लाभ दोनों का विषय है। जापान ने वर्ष 1986 में भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मुख्य कारण फल मक्खी (Fruit Fly) जैसे कीटों के संभावित संक्रमण को माना गया था। जापान की कठोर संगरोध (Quarantine) नीति के अनुसार किसी भी कृषि उत्पाद के आयात के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि उससे देश की कृषि जैव-सुरक्षा को कोई खतरा न हो। लगभग दो दशकों तक भारत और जापान के बीच तकनीकी चर्चाएं, वैज्ञानिक परीक्षण और संगरोध मानकों के अनुपालन से संबंधित प्रयास जारी रहे। अंततः वर्ष 2006 में जापान ने भारतीय आमों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया और भारतीय आमों को पुनः अपने बाजार में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। यह भारतीय बागवानी निर्यात क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

वर्ष 2026 में जापान द्वारा आयात निलंबन

वर्ष 2026 में जापान ने एक बार फिर भारतीय आमों के आयात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। जापानी निरीक्षकों द्वारा भारत के Vapour Heat Treatment (VHT) केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान कुछ प्रक्रियागत कमियां पाई गईं। यद्यपि किसी वास्तविक कीट संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी जापान ने

अपने कड़े पौध-संगरोध मानकों के अनुपालन में कमी के आधार पर यह निर्णय लिया। यह निलंबन ऐसे समय में लागू हुआ जब आम निर्यात का प्रमुख मौसम चल रहा था। परिणामस्वरूप अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और अन्य उच्च मूल्य वाली किस्मों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

किसानों पर संभावित आर्थिक प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन और बढ़ती चुनौतियां

जापान द्वारा लगाए गए आयात निलंबन का सबसे बड़ा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ सकता है। निर्यात के लिए तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले आमों को यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं मिलता, तो उन्हें घरेलू बाजार में बेचना पड़ता है। इससे बाजार में आपूर्ति बढ़ने और कीमतों में गिरावट की संभावना रहती है। निर्यात गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में किसानों और निर्यातकों द्वारा अतिरिक्त निवेश किया जाता है, जिसमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण और परिवहन शामिल हैं। निर्यात रुकने की स्थिति में यह निवेश अपेक्षित लाभ नहीं दे पाता। इसके अतिरिक्त निर्यात गतिविधियों से जुड़े पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और एयर कार्गो सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह केवल व्यापारिक नुकसान नहीं, बल्कि ग्रामीण आय और रोजगार पर भी प्रभाव डालने वाली घटना है। वर्तमान समय में आम उत्पादन केवल व्यापारिक प्रतिबंधों से ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से भी प्रभावित हो रहा है। अनियमित वर्षा, तापमान में असामान्य वृद्धि, फूल आने के समय मौसम में परिवर्तन तथा चरम मौसमी घटनाओं के कारण कई क्षेत्रों में उत्पादकता प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र में अल्फांसो आम की पैदावार में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। जब उत्पादन घटता है और साथ ही निर्यात बाजार

भी प्रभावित होता है, तब किसानों की आय पर दोहरा दबाव उत्पन्न होता है। इसलिए जलवायु-सहिष्णु बागवानी तकनीकों का विकास और प्रसार अत्यंत आवश्यक हो गया है।

निष्कर्ष और सुझाव

आम भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक रणनीतिक उत्पाद है, जो उत्पादन, रोजगार, मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत के पास उत्पादन क्षमता, जैव विविधता और बाजार मांग जैसी सभी आवश्यक शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक निर्यात में अग्रणी बनने के लिए गुणवत्ता, ट्रेसबिलिटी, कोल्ड चेन और संगरोध अवसंरचना को और मजबूत करना होगा। जापान द्वारा 2026 में लगाया गया आयात निलंबन भारतीय आम उद्योग के लिए एक चेतावनी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफलता केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि गुणवत्ता मानकों के सतत अनुपालन से प्राप्त होती है। भारतीय आम निर्यात को सुदृढ़ बनाने के लिए Vapour Heat Treatment और संगरोध सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। किसानों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, Global GAP प्रमाणन तथा निर्यात प्रक्रियाओं का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ट्रेसबिलिटी आधारित डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि खेत से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही नए निर्यात बाजारों की खोज, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की भागीदारी, कोल्ड चेन अवसंरचना का विस्तार और आम प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देकर भारतीय आम क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। यदि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक होने के साथ-साथ सबसे प्रभावशाली आम निर्यातक देश भी बन सकता है।